[2024] 8 एस.सी.आर. 955 : 2024 आईएनएससी 637

प्रेम प्रकाश

बनाम

भारतीय यूनियन माध्यम प्रवर्तन निदेशालय

(आपराधिक अपील संख्या - 3572/2024)

28 अगस्त 2024

[**बी.आर. गवई और के.वी. विश्वनाथन**,* **जे.जे.**]

विचारणीय मुद्दा

जब कोई व्यक्ति उसी जाँच एजेंसी द्वारा जाँच किए गए किसी अन्य मामले में न्यायिक हिरासत/हिरासत में हो, तो क्या दर्ज किए गए बयान (वर्तमान मामले में, दिनांक 03.08.2023, 04.08.2023, 11.08.2023 के बयान) किसी नए मामले के लिए, जिसमें उसकी गिरफ्तारी अभी तक नहीं दिखाई गई है, और जिनमें निर्माता के खिलाफ आपत्तिजनक सामग्री होने का दावा किया गया है, प्रिवेंशन ऑफ़ मनी लॉन्डरिंग अधिनियम, 2002 की धारा 50 के तहत स्वीकार्य होंगे।

हेडनोट्स †

प्रिवेंशन ऑफ़ मनी लॉन्डरिंग अधिनियम, 2002 – धारा 50 – साक्ष्य अधिनियम, 1872 – धारा 25 – अपीलकर्ता एक अन्य ई.सी.आई.आर के संबंध में 25.08.2022 से न्यायिक हिरासत में था और जब वह उपरोक्त न्यायिक हिरासत में था, तो उसकी गिरफ्तारी वर्तमान ई.सी.आई.आर में 11.08.2023 को दिखाई गई थी - अपीलकर्ता का बयान, जब वह हिरासत में था, दर्ज किया गया, यदि धारा 50 के तहत स्वीकार्य हो:

निर्णय: नहीं - जब कोई अभियुक्त पी.एम.एल.ए के तहत हिरासत में होता है, चाहे वह किसी भी मामले में हिरासत में हो, उसी जांच एजेंसी के समक्ष पी.एम.एल.ए की धारा 50 के तहत दिया गया कोई भी बयान बयान देने वाले के खिलाफ अस्वीकार्य है - उसी जांच एजेंसी द्वारा जांच की गई कार्यवाही के अनुसरण में हिरासत में लिया गया व्यक्ति स्वतंत्र दिमाग से काम करने वाला व्यक्ति नहीं है और बयान देने वाले के खिलाफ ऐसे बयानों को स्वीकार्य बनाना बेहद असुरक्षित होगा - यदि अपीलकर्ता के बयान को उसके खिलाफ दोषपूर्ण माना जाता है, तो वह साक्ष्य अधिनियम की धारा 25 के तहत आएगा क्योंकि उसने उसी जांच एजेंसी द्वारा शुरू की गई एक अन्य कार्यवाही के अनुसरण में न्यायिक हिरासत में रहते हुए बयान दिया था - चूंकि अपीलकर्ता को बयान दर्ज करने के लिए न्यायिक हिरासत से ले जाया गया था, इसलिए उसके खिलाफ बयान को स्वीकार्य बनाना न्याय का उपहास होगा - चूँकि शब्द 'कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया'

* लेखक

डिजिटल सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट्स

अनुच्छेद 21 में होने वाले 'कानून द्वारा' एक उचित और वैध प्रक्रिया होनी चाहिए - धारा 50 के तहत अपीलकर्ता के बयान पर उसके खिलाफ ईसीआईआर संख्या 5/2023 में भरोसा नहीं किया जा सकता है, भले ही अपीलकर्ता उस समय ईसीआईआर संख्या 4/2022 में हिरासत में था - इसके अलावा, सह-अभियुक्त के बयानों में ठोस सबूत का चरित्र नहीं होगा और सह-अभियुक्त के कबूलनामे से निपटने के दौरान इस न्यायालय द्वारा साक्ष्य अधिनियम की धारा 30 के तहत निर्धारित कानून लागू होगा - सह-अभियुक्त का बयान प्रथम दृष्टया बिक्री विलेख और अन्य दस्तावेजों की जालसाजी में अपीलकर्ता की भूमिका या मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध में शामिल होने के बारे में कुछ भी संकेत नहीं देता है - अपीलकर्ता ने धारा 45 के तहत दोहरी शर्तों को पूरा किया - यह मानने के लिए उचित आधार हैं कि अपीलकर्ता पी.एम.एल.ए की धारा 3 और 4 के तहत कथित मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध का दोषी नहीं है और अपीलकर्ता द्वारा कोई अपराध करने की संभावना नहीं है अपराध, यदि जमानत पर बढ़ाया गया - आक्षेपित आदेश रद्द और अपास्त - अपीलकर्ता को जमानत दी गई। [पैरा 27, 32, 34, 37, 45, 49]

प्रिवेंशन ऑफ़ मनी लॉन्डरिंग अधिनियम, 2002 – धारा 45 – इसके अंतर्गत दो शर्तें, जिन पर चर्चा की गई है - जाँच का दायरा - "विश्वास करने के लिए उचित आधार" - अर्थ:

निर्णय: पी.एम.एल.ए में ज़मानत देने के आवेदन पर विचार करते समय न्यायालय को मामले के गुण-दोष पर गहराई से विचार करने की आवश्यकता नहीं है और केवल रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री के आधार पर न्यायालय का दृष्टिकोण अपेक्षित है - धारा 45 में प्रयुक्त शब्द "विश्वास करने के लिए उचित आधार" हैं, जिसका अर्थ है कि न्यायालय को केवल यह देखना है कि क्या अभियुक्त के विरुद्ध वास्तविक मामला है और अभियोजन पक्ष को उचित संदेह से परे आरोप साबित करने की आवश्यकता नहीं है। [अनुच्छेद 13]

प्रिवेंशन ऑफ़ मनी लॉन्डरिंग अधिनियम, 2002 – जमानत आवेदन -प्रतिवाद/प्रतिक्रिया मूल न्यायालय में - महत्व:

निर्णय: ऐसे मामलों में जहां सरकारी वकील जमानत आवेदन का विरोध करने का एक सुविचारित निर्णय लेता है, जांच एजेंसी के प्रति-शपथपत्र को एक ठोस मामला बनाना चाहिए जिसमें विशेष रूप से संक्षेप में उस सामग्री को स्पष्ट किया जाना चाहिए जिस पर भरोसा किया जाना चाहिए ताकि दिए गए मामले में प्रथम दृष्टया तीन मूलभूत तथ्य स्थापित हो सकें, ताकि जमानत आवेदन के चरण में न्यायालय को विजय मदनलाल चौधरी मामले में निर्धारित ढांचे के भीतर निष्कर्ष पर पहुंचने में मदद मिल सके - इसके बाद ही धारा 24 के तहत अनुमान उत्पन्न होगा और भार अभियुक्त पर स्थानांतरित हो जाएगा। [अनुच्छेद 15]

प्रेम प्रकाश बनाम

भारतीय यूनियन माध्यम प्रवर्तन निदेशालय

उद्धृत केस लॉ

विजय मदनलाल चौधरी एवं अन्य। बनाम भारत संघ और अन्य। [2022] 6 एससीआर 382: (2022) एससीसी ऑनलाइन एससी 929; रामकृपाल मीना बनाम प्रवर्तन निदेशालय एसएलपी (क्रि.) संख्या 3205; जावेद गुलाम नबी शेख बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य, 2024 एससीसी ऑनलाइन 1693; रंजीतसिंग ब्रह्मजीतसिंग शर्मा बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य [2005] 3 एससीआर 345: (2005) 5 एससीसी 294; राजाराम जयसवाल बनाम बिहार राज्य, एआईआर 1964 एससी 828; नंदिनी सत्पथी बनाम पी.एल. दानी और अन्य [1978] 3 एससीआर 608: (1978) 2 एससीसी 424; कश्मीरा सिंह बनाम मध्य प्रदेश राज्य [1952] एससीआर 526 - पर निर्भर।

रे एलुकुरी शेषपानी चेट्टी, **आई.एल.आर 1937 मैड** 358; कोडंगी बनाम एम्पेरर, **ए.आई.आर 1932 मैड 24 - संदर्भित।**

अधिनियमों की सूची

प्रिवेंशन ऑफ़ मनी लॉन्डरिंग अधिनियम, 2002; साक्ष्य अधिनियम, 1872; दंड संहिता, 1860।

कीवर्ड की सूची

प्रिवेंशन ऑफ़ मनी लॉन्डरिंग अधिनियम, 2002 की धारा 50; प्रिवेंशन ऑफ़ मनी लॉन्डरिंग अधिनियम, 2002 की धारा 45; साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 25; भारत के संविधान का अनुच्छेद 21; धन शोधन; बिक्री विलेख की जालसाजी; न्यायिक हिरासत; उसी जांच एजेंसी द्वारा जांच किए गए किसी अन्य मामले में न्यायिक हिरासत/हिरासत में व्यक्ति; दर्ज किए गए बयानों की स्वीकार्यता; निर्माता के खिलाफ आपत्तिजनक सामग्री; सह-अभियुक्त का इकबालिया बयान; सह-अभियुक्त के बयान; जमानत; 'कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया'; "विश्वास करने के लिए उचित आधार"।

मामला उत्पन्न

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: आपराधिक अपील संख्या 3572 वर्ष 2024

झारखंड उच्च न्यायालय, रांची के दिनांक 22.03.2024 के निर्णय एवं आदेश से

बीए संख्या 9863/2023

पार्टियों में उपस्थिति

रंजीत कुमार, सिद्धार्थ अग्रवाल, वरिष्ठ अधिवक्ता, इंद्रजीत सिन्हा, सुश्री स्नेह सिंह, सुश्री अनुसूया साधु सिन्हा, सौम्या शंकर, हर्ष यादव, सिद्धार्थ नायडू, मेसर्स केएसएन एंड कंपनी, अपीलकर्ता के लिए अधिवक्ता।

एस.वी. राजू, एएसजी, ज़ोहेब हुसैन, अन्नम वेंकटेश, कानू अग्रवाल, मृगांक पाठक, सुश्री आकृति मिश्रा, अरविन्द कुमार शर्मा, प्रतिवादी के लिए अधिवक्ता।

सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

निर्णय

के.वी. विश्वनाथन, जे.

1. अनुमति प्रदान की गई।
2. वर्तमान अपील झारखंड उच्च न्यायालय, रांची के बी.ए. संख्या 9863/2023 के दिनांक 22.03.2024 के निर्णय को चुनौती देती है। उक्त निर्णय द्वारा, उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ता की ज़मानत याचिका खारिज कर दी। अपीलकर्ता ने ई.सी.आई.आर-आर.एन.जेड.ओ/10/2023 (जिसे आगे ई.सी.आई.आर मामला संख्या 5/2023 कहा जाएगा) में ई.सी.आई.आर मामला संख्या 5/2023 के संबंध में नियमित ज़मानत की मांग की थी, जो प्रिवेंशन ऑफ़ मनी लॉन्डरिंग अधिनियम, 2002 (जिसे आगे 'पी.एम.एल.ए' कहा जाएगा) की धारा 3 और 4 के तहत अपराध के लिए दर्ज किया गया था और विशेष न्यायाधीश, पी.एम.एल.ए, रांची की अदालत में लंबित था।

संक्षिप्त तथ्य

3. जिस अपराध के आधार पर 07.03.2023 को ई.सी.आई.आर संख्या 5/2023 दर्ज की गई, वह सदर पुलिस थाना मामला संख्या 399/2022 की एक प्राथमिकी है, जो 08.09.2022 को भारतीय दंड संहिता, 1860 (संक्षेप में 'आईपीसी') की धाराओं 406, 420, 467, 468, 447, 504, 506, 341, 323 और 34 के अंतर्गत दंडनीय अपराधों के लिए दर्ज की गई थी। अपीलकर्ता का नाम वहाँ अभियुक्त के रूप में नहीं था।
4. भारतीय दंड संहिता की धारा 420 और 467 के अनुसूचित अपराध होने के कारण, ई.सी.आई.आर संख्या 5/2023 दर्ज की गई और पी.एम.एल.ए के तहत जाँच शुरू की गई। यहाँ भी अपीलकर्ता का नाम नहीं लिया गया, हालाँकि ई.सी.आई.आर में कुछ अज्ञात व्यक्तियों के शामिल होने का उल्लेख था। आरोप है कि जाँच में क्रमशः सर्किल ऑफिस, बार्गेन, रांची और रजिस्ट्रार ऑफ़ एश्योरेंस, कोलकाता के मूल अभिलेखों में हेराफेरी का पता चला और इसलिए कानून के अनुसार मूल रजिस्टरों को अपने कब्जे में ले लिया गया।
5. पी.एम.एल.ए के तहत दर्ज शिकायत के लिए आरोपों का आधार इस प्रकार है:- उमेश कुमार गोप ने शिकायत की कि राजेश राय, इम्तियाज अहमद, भरत प्रसाद, लखन सिंह, पुनीत भार्गव और बिष्णु कुमार अग्रवाल ने धोखाधड़ी से प्लॉट संख्या 28, खाता संख्या 37, ग्राम गारी, चेशायर होम रोड, थाना सदर, रांची में
स्थित एक एकड़ जमीन हासिल कर ली। आरोप यह था कि आरोपी राजेश राय

प्रेम प्रकाश बनाम
भारतीय यूनियन माध्यम प्रवर्तन निदेशालय

पुत्र जगदीश राय ने अवैध और धोखाधड़ी से इम्तियाज अहमद और आरोपी भरत प्रसाद के नाम पर पावर ऑफ अटॉर्नी बनाई और उक्त पावर ऑफ अटॉर्नी के आधार पर एक जाली बिक्री विलेख तैयार किया और अपीलकर्ता के एक साथी आरोपी पुनीत भार्गव को 1,78,55,800/- रुपये में जमीन का उपर्युक्त टुकड़ा बेच दिया। यह भी आरोप लगाया गया है कि उक्त भूमि को आरोपी पुनीत भार्गव ने आरोपी बिष्णु कुमार अग्रवाल को दिनांक 01.04.2021 के दो बिक्री विलेखों के माध्यम से कुल 1,80,00,000/- रुपये (1,02,60,000/- रुपये और 77,40,000 रुपये) में हस्तांतरित कर दिया था। प्रवर्तन निदेशालय के अनुसार, आरोपी बिष्णु कुमार अग्रवाल ने आरोपी पुनीत भार्गव को उसकी फर्म शिवा फैबकॉन्स (आरोपी पुनीत भार्गव की प्रोप्राइटरशिप फर्म) के खाते में 1,78,20,000/- रुपये का भुगतान किया और जिसमें से 1,01,57,400/- रुपये मेसर्स जामिनी एंटरप्राइजेज को हस्तांतरित कर दिए गए, जो प्रतिवादी-जांच एजेंसी के अनुसार, एक ऐसी फर्म थी जिसका लाभकारी मालिक अपीलकर्ता है। जांच एजेंसी की अभियोजन शिकायत में अपीलकर्ता को आरोपी संख्या 8 के रूप में नामित किया गया था।

6. जाँच एजेंसी के अनुसार, फोरेंसिक विज्ञान निदेशालय ने पुष्टि की है कि विलेख संख्या 184/1948, एक कथित विक्रय विलेख, जिसके द्वारा उमेश गोप के पूर्वजों ने राजेश राय के पिता जगदीश राय को संपत्ति हस्तांतरित की थी, जाली है। कोलकाता के रजिस्ट्रार ऑफ एश्योरेंस की तथ्यान्वेषी समिति की रिपोर्ट के आधार पर, भारतीय दंड संहिता की धारा 120-बी, 465, 467, 468 और 471 के तहत अपराधों के लिए दिनांक 10.05.2023 को कोलकाता के हरे स्ट्रीट पुलिस स्टेशन में एक अलग प्राथमिकी संख्या 137/2023 दर्ज की गई। बताया गया है कि उक्त प्राथमिकी को ई.सी.आई.आर संख्या 5/2023 में भी शामिल कर लिया गया था।

7. यह आरोप लगाया गया है कि अपीलकर्ता के निर्देश पर ही राजेश राय द्वारा पुनीत भार्गव के पक्ष में 1,78,55,800/- रुपये की राशि का विक्रय विलेख निष्पादित किया गया था; शिवा फैबकॉन्स (पुनीत भार्गव की स्वामित्व वाली फर्म) से राजेश राय को केवल 25 लाख रुपये हस्तांतरित किए गए थे, जबकि प्रतिफल राशि 1,78,55,800/- रुपये थी और इसे विक्रय विलेख में भुगतान किया गया दिखाया गया था; 25 लाख रुपये की उपरोक्त राशि में से 18 लाख रुपये की राशि राजेश राय के बैंक खाते से ग्रीन ट्रेडर्स (मोहम्मद सद्दाम हुसैन के नियंत्रण में साझेदारी फर्म) के बैंक खाते में हस्तांतरित की गई थी; राजेश राय द्वारा चेक के माध्यम से 7 लाख रुपये नकद निकाले गए थे; अपीलकर्ता के निर्देश पर, संपत्ति का

उत्परिवर्तन पुनीत भार्गव के नाम पर किया गया था, जो अपीलकर्ता का एक सहयोगी था; पुनीत भार्गव ने दो महीने के भीतर बिष्णु कुमार अग्रवाल को 1.80 करोड़ रुपये में संपत्ति बेच दी; 05.04.2021 को मेसर्स चालिस रियल एस्टेट (बिष्णु कुमार अग्रवाल की कंपनी) के खाते से पुनीत भार्गव के बैंक खाते में 56,62,600/- रुपये की राशि का भुगतान किया गया और 24.06.2021 को आदर्श हाइट्स प्राइवेट लिमिटेड (बिष्णु अग्रवाल की कंपनी) के खाते से पुनीत भार्गव के बैंक खाते में 1,01,57,400/- रुपये की राशि स्थानांतरित की गई; पूरा भुगतान अप्रैल और जून, 2021 के महीने में किया गया था, लेकिन पंजीकरण 1 अप्रैल, 2021 को विचार की प्राप्ति से पहले किया गया था। अंत में, यह आरोप लगाया गया है कि 1,01,57,400/- रुपये की राशि मेसर्स जामिनी एंटरप्राइजेज के बैंक खाते में स्थानांतरित की गई थी, जो कि अपीलकर्ता - प्रेम प्रकाश द्वारा नियंत्रित और लाभकारी रूप से स्वामित्व वाली फर्म बताई जाती है।

8. आरोप है कि अपीलकर्ता ने अन्य अभियुक्तों, अफ़शर अली उर्फ़ अफ़सू खान, राजेश राय, लखन सिंह, इम्तियाज़ अहमद, भरत प्रसाद, सद्दाम हुसैन, पुनीत भार्गव, छवि रंजन और बिष्णु कुमार अग्रवाल के साथ मिलकर ज़मीन-जायदाद के रूप में अपराध की आय अर्जित करने की साजिश रची। यह विशेष रूप से आरोप लगाया गया है कि बिष्णु कुमार अग्रवाल का सहयोगी होने के नाते अपीलकर्ता ने बिष्णु कुमार अग्रवाल को ज़मीन अधिग्रहण में सहायता करने के लिए अपने संबंधों का इस्तेमाल किया और बिष्णु कुमार अग्रवाल ने यह धनराशि पुनीत भार्गव को हस्तांतरित की और फिर यह राशि जामिनी एंटरप्राइजेज को हस्तांतरित कर दी गई।

9. अपीलकर्ता को 11.08.2023 को हिरासत में लिया गया था। वह पहले से ही 25.08.2022 से ईसीआईआर संख्या 4/2022 के तहत हिरासत में था। उसकी ज़मानत की अर्ज़ी विशेष न्यायाधीश ने 20.09.2023 को खारिज कर दी थी। उसने उच्च न्यायालय में ज़मानत अर्ज़ी दायर की थी। उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ता की ज़मानत याचिका खारिज कर दी है। व्यथित होकर, अपीलकर्ता हमारे सामने है।

10. हमने अपीलकर्ता के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रंजीत कुमार को सुना है, जिन्हें विद्वान अधिवक्ता श्री इंद्रजीत सिन्हा और श्री सिद्धार्थ नायडू ने कुशलतापूर्वक सहायता प्रदान की। हमने प्रतिवादियों की ओर से विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल श्री एस.वी. राजू को भी सुना है, जिन्हें श्री ज़ोहेब हुसैन और श्री कानू अग्रवाल ने कुशलतापूर्वक सहायता प्रदान की। दोनों पक्षों के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने अपने-अपने तर्क प्रस्तुत किए हैं और विस्तृत लिखित प्रस्तुतियाँ भी प्रस्तुत की हैं।

प्रेम प्रकाश बनाम

भारतीय यूनियन माध्यम प्रवर्तन निदेशालय

धारा 45 पी.एम.एल.ए-कॉन्टूर्स

11. यह देखते हुए कि यह पी.एम.एल.ए की धारा 45 के तहत अपराध के लिए एक जमानत आवेदन है, इसमें उल्लिखित दो शर्तें प्रासंगिक हो जाती हैं। पी.एम.एल.ए की धारा 45(1) इस प्रकार है:-|

"**45. अपराधों का संज्ञेय और अजमानतीय होना।** (1) किसी बात के होते हुए भी दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) अधिनियम के अंतर्गत किसी अपराध के आरोपी किसी भी व्यक्ति को जमानत पर या अपने स्वयं के बांड पर तब तक रिहा नहीं किया जाएगा जब तक कि-

I. लोक अभियोजक को ऐसी रिहाई के आवेदन का विरोध करने का अवसर दिया गया है; और

II. जहाँ लोक अभियोजक आवेदन का विरोध करता है, वहाँ न्यायालय संतुष्ट है कि यह मानने के लिए उचित आधार हैं कि वह ऐसे अपराध का दोषी नहीं है और यह कि जमानत पर रहते हुए उसके द्वारा कोई अपराध करने की संभावना नहीं है:

बशर्ते कि कोई व्यक्ति, जो सोलह वर्ष से कम आयु का है, या महिला है, या बीमार या अशक्त है, या जिस पर अकेले या अन्य सह-अभियुक्तों के साथ एक करोड़ रुपये से कम की धनराशि के धन शोधन का आरोप है, जमानत पर रिहा किया जा सकता है, यदि विशेष न्यायालय ऐसा निर्देश दे:

आगे यह भी प्रावधान है कि विशेष न्यायालय धारा 4 के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का संज्ञान तब तक नहीं लेगा जब तक कि निम्नलिखित द्वारा लिखित रूप में शिकायत न की गई हो-

I. निदेशक; या

II. केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार का कोई अधिकारी, जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त उस सरकार द्वारा किए गए किसी सामान्य या विशेष आदेश द्वारा लिखित रूप में प्राधिकृत किया गया हो।

विजय मदनलाल चौधरी एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य (2022) एससीसी ऑनलाइन एससी 929 में प्रकाशित मामले में, इस न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा कि पी.एम.एल.ए की धारा 45 अभियुक्त के ज़मानत देने के अधिकार को प्रतिबंधित करती है, लेकिन यह नहीं कहा जा सकता कि धारा 45 के तहत प्रदान की गई शर्तें ज़मानत देने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाती हैं। पैरा 131 नीचे उद्धृत है:-

"**131.** यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि 2002 अधिनियम की धारा 45 के तहत प्रदान की गई दो शर्तें, यद्यपि अभियुक्त के ज़मानत देने के अधिकार को प्रतिबंधित करती हैं, लेकिन यह नहीं कहा जा सकता कि धारा 45 के

तहत प्रदान की गई शर्तें ज़मानत देने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाती हैं। विवेकाधिकार न्यायालय में निहित है, जो मनमाना या तर्कहीन नहीं, बल्कि न्यायिक है, जो 2002 अधिनियम की धारा 45 के तहत प्रदत्त विधि के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित है। ..."

ये टिप्पणियाँ महत्वपूर्ण हैं और यदि इन्हें इस न्यायालय द्वारा आपराधिक अपील संख्या 3295/2024 [**मनीष सिसोदिया (II)** बनाम **प्रवर्तन निदेशालय**] में दिनांक 09.08.2024 को दिए गए हालिया फैसले के संदर्भ में पढ़ा जाए, तो यह पूरी तरह स्पष्ट हो जाएगा कि पी.एम.एल.ए के तहत भी शासन सिद्धांत यही है कि "जमानत नियम है और जेल अपवाद है"। **[मनीष सिसोदिया (II)]** के पैरा 53 में, इस न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी की:-

"53...हमारे अनुभव से, हम कह सकते हैं कि ऐसा प्रतीत होता है कि निचली अदालतें और उच्च न्यायालय ज़मानत देने के मामलों में सावधानी बरतने का प्रयास करते हैं। यह सिद्धांत कि ज़मानत एक नियम है और इनकार एक अपवाद है, कई बार उल्लंघन के रूप में अपनाया जाता है। सीधे-सादे मामलों में भी ज़मानत न दिए जाने के कारण, इस न्यायालय में ज़मानत याचिकाओं की भारी संख्या जमा हो जाती है, जिससे लंबित मामलों की संख्या और भी बढ़ जाती है। अब समय आ गया है कि निचली अदालतें और उच्च न्यायालय इस सिद्धांत को स्वीकार करें कि "ज़मानत नियम है और जेल अपवाद है।"

पी.एम.एल.ए की धारा 45 में केवल इतना उल्लेख है कि कुछ शर्तों को पूरा किया जाना है। यह सिद्धांत कि, "जमानत नियम है और जेल अपवाद है" केवल भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 का एक व्याख्या है, जिसमें कहा गया है कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही किसी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित किया जाएगा। व्यक्ति की स्वतंत्रता हमेशा एक नियम है और वंचना अपवाद है। वंचना केवल कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया द्वारा हो सकती है, जिसे एक वैध और उचित प्रक्रिया होनी चाहिए। पी.एम.एल.ए की धारा 45 दोहरी शर्तों को लागू करके इस सिद्धांत को फिर से नहीं लिखती है जिसका अर्थ है कि वंचना आदर्श है और स्वतंत्रता अपवाद है। जैसा कि पहले निर्धारित किया गया है, आवश्यक केवल यह है कि जिन मामलों में जमानत दोहरी शर्तों की संतुष्टि के अधीन है, उन शर्तों को पूरा किया जाना चाहिए।

12. स्वतंत्र रूप से और जैसा कि **मनीष सिसोदिया (II) (सुप्रा)** में **रामकृपाल मीणा** बनाम **प्रवर्तन निदेशालय** (एसएलपी (आपराधिक) संख्या 3205/2024 दिनांक

30.07.2024) और **जावेद गुलाम नबी शेख** बनाम **महाराष्ट्र राज्य और अन्य,** 2024 एससीसी ऑनलाइन 1693 पर भरोसा करते हुए जोरदार ढंग से दोहराया गया है, जहां अभियुक्त पहले से ही काफी महीनों से हिरासत में है और कम समय के भीतर मुकदमे के समापन की कोई संभावना नहीं है, पी.एम.एल.ए की धारा 45 की कठोरता को सशर्त स्वतंत्रता प्रदान करने के लिए उपयुक्त रूप से शिथिल किया जा सकता है। इसके अलावा, **मनीष सिसोदिया (II) (सुप्रा)** ने **जावेद गुलाम नबी शेख (सुप्रा)** मामले में दिए गए फैसले को दोहराया कि मुकदमे को जल्द पूरा करने की उम्मीद में लोगों को असीमित समय तक सलाखों के पीछे रखना, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत व्यक्तियों के मौलिक अधिकार का हनन होगा और दोषी ठहराए जाने से पहले लंबे समय तक कारावास को बिना मुकदमे के सजा नहीं बनने दिया जाना चाहिए। दरअसल, **मनीष सिसोदिया (II) (सुप्रा)** ने **मनीष सिसोदिया (I)** बनाम **प्रवर्तन निदेशालय** (आपराधिक अपील संख्या 3352/2023 में दिनांक 30.10.2023 का निर्णय) मामले में दिए गए फैसले को दोहराया, जहाँ निम्नलिखित निर्णय दिया गया था:-

> "28. किसी अपराध का दोषी ठहराए जाने से पहले नज़रबंदी या जेल जाना बिना मुकदमे के सज़ा नहीं बन जाना चाहिए। यदि अभियोजन पक्ष के आश्वासन के बावजूद मुकदमा लंबा खिंचता है, और यह स्पष्ट है कि मामले का फैसला निश्चित समय में नहीं होगा, तो ज़मानत की प्रार्थना योग्य हो सकती है। हालाँकि अभियोजन पक्ष आर्थिक अपराध से संबंधित हो सकता है, फिर भी इन मामलों को मृत्युदंड, आजीवन कारावास, दस साल या उससे अधिक की सज़ा जैसे स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के तहत अपराधों, हत्या, बलात्कार, डकैती, फिरौती के लिए अपहरण, सामूहिक हिंसा आदि के समान मानना उचित नहीं होगा। यह ऐसा मामला भी नहीं है जहाँ सैकड़ों/हज़ारों जमाकर्ताओं के साथ धोखाधड़ी की गई हो। आरोपों को स्थापित और सिद्ध किया जाना चाहिए। देरी के मामलों में ज़मानत का अधिकार, साथ ही आरोपों की प्रकृति के आधार पर लंबी अवधि के लिए कारावास, संहिता की धारा 439 और पीएमएल अधिनियम की धारा 45 में शामिल होना चाहिए। इसका कारण यह है कि संवैधानिक अधिदेश सर्वोच्च कानून है, और यह उस व्यक्ति का मूल अधिकार है जिस पर किसी अपराध का आरोप लगाया गया है और जो दोषी नहीं है, कि उसकी शीघ्र सुनवाई सुनिश्चित की जाए और उसे शीघ्र सुनवाई मिले। जब मुकदमा अभियुक्त के अलावा अन्य कारणों से आगे नहीं बढ़ रहा हो, तो अदालत को, जब तक कि उचित कारण न हों, ज़मानत देने के अधिकार का प्रयोग करने

के लिए निर्देशित किया जा सकता है। यह बात वहाँ अधिक सत्य होगी जहाँ मुकदमे में वर्षों लग सकते हैं।"

इसी पृष्ठभूमि में पी.एम.एल.ए की धारा 45 को समझने और लागू करने की आवश्यकता है। अनुच्छेद 21 एक उच्च संवैधानिक अधिकार होने के नाते, वैधानिक प्रावधानों को उक्त उच्च संवैधानिक आदेश के अनुरूप होना चाहिए।

पी.एम.एल.ए की धारा 45 के तहत जांच का दायरा

13. धारा 45 के तहत जांच के दायरे पर वापस आते हुए, विजय मदनलाल चौधरी (सुप्रा) ने रणजीतसिंह ब्रह्मजीतसिंह शर्मा बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य (2005) 5 एससीसी 294 में रिपोर्ट किए गए फैसले को दोहराते और उससे सहमत होते हुए कहा कि पी.एम.एल.ए में जमानत देने के आवेदन पर विचार करते समय न्यायालय को मामले के गुण-दोष पर गहराई से विचार करने की आवश्यकता नहीं है और केवल रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री के आधार पर न्यायालय का दृष्टिकोण आवश्यक है। इसने माना कि न्यायालय को केवल जांच के दौरान एकत्र की गई उचित सामग्री के आधार पर संभावना के आधार पर अपना दृष्टिकोण रखने की आवश्यकता है। धारा 45 में प्रयुक्त शब्द "विश्वास करने के लिए उचित आधार" हैं, जिसका अर्थ है कि न्यायालय को केवल यह देखना है कि क्या अभियुक्त के खिलाफ कोई वास्तविक मामला है और अभियोजन पक्ष को उचित संदेह से परे आरोप साबित करने की आवश्यकता नहीं है।

"131. यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि 2002 अधिनियम की धारा 45 के तहत प्रदान की गई दोहरी शर्तें, यद्यपि अभियुक्त के ज़मानत देने के अधिकार को प्रतिबंधित करती हैं, लेकिन यह नहीं कहा जा सकता कि धारा 45 के तहत प्रदान की गई शर्तें ज़मानत देने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाती हैं। विवेकाधिकार न्यायालय में निहित है जो मनमाना या तर्कहीन नहीं बल्कि न्यायिक है, जो 2002 अधिनियम की धारा 45 के तहत प्रदत्त विधि के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित है। मकोका में दोहरी शर्तों को निर्धारित करने वाले एक समान प्रावधान पर विचार करते हुए, इस न्यायालय ने रणजीतसिंह ब्रह्मजीतसिंह शर्मा (सुप्रा) में निम्नलिखित निर्णय दिया:

"44. हमारी राय में, धारा 21(4) के शब्दों से यह निष्कर्ष नहीं निकलता कि अदालत को इस निष्कर्ष पर पहुँचना ही होगा कि ज़मानत के लिए आवेदक ने अधिनियम के तहत कोई अपराध नहीं किया है। यदि ऐसी व्याख्या की जाती है, तो ज़मानत देने का इरादा रखने वाली अदालत को इस निष्कर्ष पर पहुँचना ही होगा कि आवेदक ने ऐसा कोई अपराध नहीं किया है। ऐसी स्थिति में, अभियोजन पक्ष के लिए आवेदक को दोषसिद्धि का निर्णय प्राप्त करना असंभव होगा। विधानमंडल की ऐसी मंशा नहीं हो सकती। इसलिए,

एम.सी.ओ.सी.ए. की धारा 21(4) की व्याख्या तर्कसंगत रूप से की जानी चाहिए। इसकी व्याख्या इस प्रकार की जानी चाहिए कि अदालत मुक़दमा शुरू होने से बहुत पहले ही दोषसिद्धि और दोषसिद्धि के फ़ैसले और ज़मानत देने के आदेश के बीच एक नाज़ुक संतुलन बनाए रख सके। इसी प्रकार, अदालत को ज़मानत दिए जाने के बाद उसके अपराध करने की संभावना के बारे में भी निष्कर्ष दर्ज करना होगा। हालाँकि, भविष्य में ऐसा अपराध अधिनियम के तहत एक अपराध होना चाहिए, न कि कोई अन्य अपराध। चूँकि किसी अभियुक्त के भविष्य के आचरण की भविष्यवाणी करना कठिन है, इसलिए अदालत को इस पहलू पर विचार करना ही होगा। यह मामला अभियुक्त के पूर्ववृत्त, उसकी प्रवृत्ति और उस प्रकृति तथा तरीके को ध्यान में रखते हुए है, जिससे उस पर अपराध करने का आरोप है।

45. इसके अतिरिक्त, यह भी सामान्य बात है कि जमानत देने के लिए आवेदन पर विचार करने के प्रयोजनार्थ, यद्यपि विस्तृत कारण बताना आवश्यक नहीं है, जमानत देने के आदेश में कम से कम गंभीर मामलों में विवेक का प्रयोग प्रदर्शित किया जाना चाहिए कि आवेदक को जमानत का विशेषाधिकार क्यों दिया गया या क्यों नहीं दिया गया।

46. इस स्तर पर न्यायालय का कर्तव्य साक्ष्यों का सूक्ष्मता से मूल्यांकन करना नहीं, बल्कि व्यापक संभावनाओं के आधार पर किसी निष्कर्ष पर पहुँचना है। हालाँकि, मकोका जैसे विशेष कानून पर विचार करते समय, अधिनियम की धारा 21 की उप-धारा (4) में निहित प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, न्यायालय को मामले की गहन जाँच करनी पड़ सकती है ताकि वह इस निष्कर्ष पर पहुँच सके कि जाँच के दौरान अभियुक्त के विरुद्ध एकत्रित सामग्री दोषसिद्धि के निर्णय को उचित नहीं ठहरा सकती। ज़मानत देते या अस्वीकार करते समय न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष निस्संदेह अस्थायी प्रकृति के होंगे, जिनका मामले के गुण-दोष पर कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता है और इस प्रकार, निचली अदालत मुकदमे में प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर मामले का निर्णय करने के लिए स्वतंत्र होगी, बिना किसी पूर्वाग्रह के।

हम रणजीतसिंह ब्रह्मजीतसिंह शर्मा (सुप्रा) मामले में न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणी से सहमत हैं। ज़मानत देने के आवेदन पर विचार करते समय न्यायालय को मामले के गुण-दोषों पर गहराई से विचार करने की आवश्यकता नहीं है और केवल अभिलेखों में उपलब्ध सामग्री के आधार पर

न्यायालय का दृष्टिकोण आवश्यक है। न्यायालय अभियुक्त को दोषी ठहराने के लिए साक्ष्यों का मूल्यांकन नहीं करेगा, जो कि निःसंदेह, विचारण न्यायालय का कार्य है। न्यायालय को केवल जाँच के दौरान एकत्रित उचित सामग्री के आधार पर संभाव्यता के आधार पर अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करना आवश्यक है और उक्त दृष्टिकोण को विचारण न्यायालय द्वारा मुकदमे के दौरान प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर दोष या दोषमुक्ति का निर्णय दर्ज करते समय ध्यान में नहीं रखा जाएगा। जैसा कि निम्मगड्डा प्रसाद (सुप्रा) मामले में इस न्यायालय द्वारा स्पष्ट किया गया है, 2002 के अधिनियम की धारा 45 में प्रयुक्त शब्द "विश्वास करने के उचित आधार" हैं, जिसका अर्थ है कि न्यायालय को केवल यह देखना है कि क्या अभियुक्त के विरुद्ध कोई वास्तविक मामला है और अभियोजन पक्ष को आरोप को उचित संदेह से परे साबित करने की आवश्यकता नहीं है।

पी.एम.एल.ए की धारा 24 के अंतर्गत मूलभूत तथ्यों का महत्व

14. विजय मदनलाल चौधरी (सुप्रा) मामले में पी.एम.एल.ए की धारा 24 से संबंधित तीन न्यायाधीशों की पीठ ने निम्नलिखित निर्णय दिया था:

97. जैसा भी हो, अब हम 2002 के अधिनियम की धारा 24 के तात्पर्य को समझने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। सबसे पहले, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि दोनों ही मामलों में कानूनी धारणा धन-शोधन में अपराध की आय की संलिप्तता के बारे में है। यह तथ्य तभी प्रासंगिक हो जाता है, जब अभियोजन पक्ष या प्राधिकारी कम से कम तीन बुनियादी या आधारभूत तथ्य स्थापित करने में सफल रहे हों। पहला, कि किसी अनुसूचित अपराध से संबंधित आपराधिक गतिविधि की गई है। दूसरा, कि विचाराधीन संपत्ति किसी व्यक्ति द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उस आपराधिक गतिविधि के परिणामस्वरूप प्राप्त की गई है। तीसरा, संबंधित व्यक्ति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उक्त संपत्ति से जुड़ी किसी भी प्रक्रिया या गतिविधि में शामिल है, जो अपराध की आय है। यह तथ्य स्थापित होने पर कि अपराध की आय मौजूद थी और संबंधित व्यक्ति उससे जुड़ी किसी भी प्रक्रिया या गतिविधि में शामिल था, अपने आप में धन-शोधन का अपराध बनता है। प्रक्रिया या गतिविधि की प्रकृति को अब वित्त (संख्या 2) अधिनियम, 2019 के तहत सम्मिलित स्पष्टीकरण के रूप में विस्तृत किया गया है। 2002 के अधिनियम की धारा 24 के अनुसार इन मूलभूत तथ्यों को स्थापित करने पर, यह कानूनी धारणा उत्पन्न होगी कि अपराध की ऐसी आय धन-शोधन में शामिल है। यह तथ्य कि संबंधित व्यक्ति का अपराध की ऐसी आय से

कोई कारणात्मक संबंध नहीं था और वह इस संबंध में साक्ष्य प्रस्तुत करके, उससे जुड़ी किसी भी प्रक्रिया या गतिविधि में अपनी संलिप्तता के तथ्य को गलत साबित करने में सक्षम है, कानूनी धारणा का खंडन हो जाएगा।

99. कृपया ध्यान दें कि 2002 के अधिनियम की धारा 24(ए) के तहत कानूनी धारणा तब लागू होगी जब व्यक्ति पर धन शोधन के अपराध का आरोप लगाया जाता है और अपराध की आय से जुड़ी किसी भी प्रक्रिया या गतिविधि में उसकी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष भागीदारी स्थापित हो जाती है। इसलिए, अपराध की आय का अस्तित्व एक आधारभूत तथ्य है, जिसे अभियोजन पक्ष द्वारा स्थापित किया जाना है, जिसमें उससे जुड़ी किसी भी प्रक्रिया या गतिविधि में व्यक्ति की भागीदारी भी शामिल है। एक बार जब अभियोजन पक्ष द्वारा इन आधारभूत तथ्यों को स्थापित कर दिया जाता है, तो धन शोधन के अपराध के आरोप का सामना कर रहे व्यक्ति पर यह दायित्व आ जाता है कि वह अपने व्यक्तिगत ज्ञान के अनुसार साक्ष्य प्रस्तुत करके इस कानूनी धारणा का खंडन करे कि अपराध की आय धन शोधन में शामिल नहीं है। दूसरे शब्दों में, "मानना" पद निर्णायक नहीं है। इससे यह भी नहीं निकलता कि यह कानूनी धारणा कि अपराध की आय धन शोधन में शामिल है, प्राधिकरण या न्यायालय द्वारा लागू की जानी चाहिए, बिना व्यक्ति को अपने व्यक्तिगत ज्ञान के आधार पर साक्ष्य प्रस्तुत करके इसका खंडन करने का अवसर दिए।

100. ऐसा दायित्व साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 के तात्पर्य से भी निकलता है। जिसके तहत, उसे कानूनी अनुमान का खंडन उस तरीके से करना होगा जैसा वह करना चाहता है और जैसा कि कानून में अनुमेय है, जिसमें 1973 संहिता की धारा 313 के तहत जवाब देना या अभियोजन पक्ष के गवाहों से जिरह करना भी शामिल है। व्यक्ति को प्राधिकरण या अदालत के समक्ष कार्यवाही में पर्याप्त अवसर मिलेगा, जैसा भी मामला हो। वह यह दिखाकर अपने दायित्व का निर्वहन कर सकता है कि वह अपराध की आय से जुड़ी किसी भी प्रक्रिया या गतिविधि में शामिल नहीं है। किसी भी मामले में, साक्ष्य अधिनियम की धारा 114 के अनुसार, अदालत के लिए किसी भी तथ्य के अस्तित्व की उपधारणा करना खुला है, जिसके बारे में वह सोचता है कि वह घटित हुआ होगा, विशेष मामले के तथ्यों के संबंध में प्राकृतिक घटनाओं, मानवीय आचरण और सार्वजनिक और निजी व्यवसाय के सामान्य क्रम को ध्यान में रखते हुए। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, विचाराधीन

प्रावधान [धारा 24 (ए)] को किसी भी मानक से अनुचित नहीं कहा जा सकता है, और न ही स्पष्ट रूप से मनमाना और असंवैधानिक कहा जा सकता है।"

मूल न्यायालय में दायर जमानत आवेदन के प्रतिवाद का महत्व

15. अभियोजन पक्ष को जिन तीन मूलभूत तथ्यों को स्थापित करने की आवश्यकता है, उनके महत्व को देखते हुए, मूल न्यायालय में जमानत आवेदन का प्रतिवाद/प्रतिक्रिया पी.एम.एल.ए जमानत मामलों में बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे मामलों में जहां सरकारी अभियोजक जमानत आवेदन का विरोध करने का एक विचारित निर्णय लेता है, जांच एजेंसी के प्रति हलफनामे से एक ठोस मामला बनना चाहिए कि कैसे ऊपर दिए गए तीन मूलभूत तथ्य दिए गए मामले में प्रथम दृष्टया स्थापित होते हैं ताकि जमानत आवेदन के चरण में न्यायालय को **विजय मदनलाल चौधरी (सुप्रा)** में निर्धारित ढांचे के भीतर निष्कर्ष पर पहुंचने में मदद मिल सके। इसके बाद ही धारा 24 के तहत अनुमान उत्पन्न होगा और भार अभियुक्त पर स्थानांतरित हो जाएगा। जमानत आवेदन के प्रतिवाद में विशेष रूप से संक्षेप में उन सामग्रियों को स्पष्ट रूप से स्पष्ट किया जाना चाहिए जिन पर प्रथम दृष्टया तीन मूलभूत तथ्यों को स्थापित करने के लिए भरोसा किया जाना है। आधारभूत तथ्य सामने आने के बाद ही अभियुक्त को धारा 45 के स्तर पर जांच के मानदंडों के अंतर्गत न्यायालय को यह विश्वास दिलाने का दायित्व होगा कि उसके द्वारा बताए गए कारणों के आधार पर यह मानने के लिए उचित आधार हैं कि वह ऐसे अपराध का दोषी नहीं है।

विश्लेषण और कारण

16. अभियोजन पक्ष का तर्क है कि (i) अपीलकर्ता ने आरोपी व्यक्तियों, अर्थात् अफसर अली, सद्दाम हुसैन और अन्य के साथ मिलीभगत की, जिन्होंने जाली बिक्री विलेख संख्या 184 /1948 बनाई, और बिक्री विलेख के आधार पर राजेश राय (अफशर अली के सहयोगी) द्वारा अपीलकर्ता के करीबी सहयोगी पुनीत भार्गव को संपत्ति बेच दी गई; (ii) राजेश राय के बैंक खाते में 25 लाख रुपये स्थानांतरित किए गए और बाद में 18 लाख रुपये (25 लाख में से) मेसर्स ग्रीन ट्रेडर्स के बैंक खाते में स्थानांतरित कर दिए गए, जो कि मोहम्मद सद्दाम हुसैन द्वारा नियंत्रित एक फर्म है, जबकि बिक्री का मूल्य 1,78,55,800/- रुपये था; (iii) अपीलकर्ता को अफसर अली और अन्य द्वारा की गई जालसाजी के बारे में पता है और उसने जानबूझकर पुनीत भार्गव के नाम पर संपत्ति हासिल की, जिसने बाद में 2 महीने के भीतर संपत्ति बिष्णु अग्रवाल को 1,50,000 रुपये में बेच दी।

1.80 करोड़ और उक्त राशि में से, 1,01,57,400/- रुपये पुनीत भार्गव द्वारा मेसर्स जामिनी एंटरप्राइजेज को हस्तांतरित किए गए, जो अपीलकर्ता द्वारा नियंत्रित और लाभकारी रूप से स्वामित्व वाली एक फर्म है; (iv) कि आरोपी व्यक्तियों को लेन-देन की पूरी जानकारी थी, क्योंकि बिक्री विलेख पुनीत भार्गव के पक्ष में 06.02.2021 को आरोपी राजेश राय के माध्यम से निष्पादित किया गया था, भुगतान 12.02.2021 को किया गया था और राजेश राय को केवल 25 लाख का भुगतान किया गया था और म्यूटेशन किया गया था और उसके बाद बिष्णु अग्रवाल को बेच दिया गया था और सभी भुगतान पुनीत भार्गव द्वारा प्राप्त किए गए थे; (v) कि बाद में कोई भुगतान नहीं किया जाना था, क्योंकि अभियोजन पक्ष के अनुसार, सभी संबंधित जानते थे कि विलेख नकली थे, और (vi) कि बिष्णु अग्रवाल ने अप्रैल और जून 2021 के महीने में भुगतान किया था

(जोर दिया गया)

17. अभियोजन पक्ष ने अफशर अली, राजदीप कुमार, मोहम्मद सद्दाम हुसैन, पुनीत भार्गव और स्वयं अपीलकर्ता के पी.एम.एल.ए की धारा 50 के तहत दिए गए बयानों पर भरोसा किया है। वे अन्य आरोपियों, अफशर अली और राजदीप कुमार, के कॉल डिटेल रिकॉर्ड पर भी भरोसा करते हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि अपीलकर्ता ने एक अन्य आरोपी छवि रंजन की मदद से, अंचल अधिकारियों को प्रभावित करके ज़मीन का दाखिल-खारिज करवाया और इसलिए, अभियोजन पक्ष के अनुसार, अपीलकर्ता की भूमिका महत्वपूर्ण है।

18. प्रतिवादी के विद्वान ए.एस.जी. ने हमें प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दायर शिकायत में उल्लिखित ऊपर उल्लिखित व्यक्तियों के बयानों का सारांश प्रस्तुत किया है।

अपीलकर्ता के बयान की स्वीकार्यता

19. मौखिक प्रस्तुतियों में और जैसा कि प्रतिवादी-प्रवर्तन निदेशालय द्वारा विस्तृत लिखित प्रस्तुतियों में बताया गया है, अपीलकर्ता के बयानों पर भरोसा करने की कोशिश की गई है। अपीलकर्ता की ओर से इसका कड़ा विरोध यह तर्क देकर किया गया है कि अपीलकर्ता ई.सी.आई.आर संख्या 4/2022 में 25 अगस्त 2022 से हिरासत में था; वर्तमान मामले में उसकी गिरफ्तारी 11 अगस्त 2023 को दिखाई गई थी और यह प्रस्तुत किया गया है कि हिरासत में दर्ज किए गए बयान (हालांकि ई.सी.आई.आर संख्या 4/2022 में) स्वीकार्य नहीं होंगे और धारा 25 के

अंतर्गत आएंगे। अपीलकर्ता-प्रेम प्रकाश का बयान, जिसका सारांश, जैसा कि शिकायत में दिया गया है, इस प्रकार है:-

> "**8.23 प्रेम प्रकाश** - बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार, होटवार, रांची में न्यायिक हिरासत में दर्ज अपने बयान दिनांक 04.08.2023 (आर.यू.डी संख्या 41) में, उन्होंने कहा कि वे बिष्णु कुमार अग्रवाल को एक व्यवसायी के रूप में जानते हैं और कभी-कभी, वे उनसे विवाह समारोहों में मिले हैं। उन्होंने आगे कहा कि पुनीत भार्गव उनके छोटे भाई जैसे हैं और वे उनके पैतृक स्थान से हैं, इसलिए वे उन्हें बचपन से जानते हैं।
>
> उनके दिनांक 03.08.2023 के बयान (आर.यू.डी संख्या 40) से पता चलता है कि अफ़शर अली समेत तीन लोग चेशायर होम रोड स्थित संपत्ति के लिए उनसे मिलने आते थे। उन्होंने उन्हें राजदीप कुमार से मिलवाया और संपत्ति का सत्यापन करवाया। कुछ समय बाद, पुनीत भार्गव की सहमति से, उन्होंने संपत्ति पुनीत भार्गव के नाम पर पंजीकृत करवा ली और बाद में यह संपत्ति बिष्णु कुमार अग्रवाल को 1.78 करोड़ रुपये की कीमत पर बेच दी गई। उनके बयान से यह भी पता चलता है कि राजदीप, ज़मीन-जायदाद के लिए छवि रंजन के निर्देश पर उनसे मिलने आते थे। हालाँकि, 15.08.2023 के अपने बयान में, उन्होंने अफ़शर अली, मोहम्मद सद्दाम हुसैन और अन्य लोगों के साथ छवि रंजन की मुलाकात के बारे में तथ्य छिपाना शुरू कर दिया।
>
> यह उल्लेखनीय है कि राजदीप प्रेम प्रकाश के अधीन उनके कर्मचारी के रूप में काम करता था और प्रेम प्रकाश के निर्देश पर आरोपी अफशर अल और मोहम्मद सद्दाम हुसैन के साथ आरोपी छवि रंजन के कार्यालय गया था। राजदीप कुमार ने 24.04.2023 को दर्ज पी.एम.एल.ए, 2002 की धारा 50 के तहत अपने बयान में भी इस तथ्य को स्वीकार किया है। (आर.यू.डी संख्या - 76)। इसके अलावा, सीडीआर की जाँच के दौरान कई कॉल की पहचान भी हुई है, जिनका उल्लेख नीचे संबंधित अनुच्छेद में भी किया गया है।
>
> (जोर दिया गया)

20. 04.08.2023 के अपने बयान में, उन्होंने कहा कि वह बिष्णु कुमार अग्रवाल को जानते थे और उनसे विवाह समारोहों के दौरान मिले थे; पुनीत भार्गव उनके छोटे भाई की तरह थे जो उनके मूल स्थान से थे और वह उन्हें बचपन से जानते थे। 03.08.2023 के अपने बयान में, उन्होंने कहा कि अफसर अली सहित व्यक्ति चेशायर होम संपत्ति के लिए उनसे मिलने आते थे और उन्होंने उन्हें राजदीप कुमार से मिलवाया और संपत्ति का सत्यापन कराया। पुनीत भार्गव की सहमति से उन्होंने संपत्ति पुनीत भार्गव के नाम पर पंजीकृत करवाई और बाद में संपत्ति बिष्णु कुमार अग्रवाल को 1.78 करोड़ रुपये में बेच दी गई। संक्षेप में, बयान को इस रूप में लिया जाए तो प्रथम दृष्टया अपीलकर्ता के खिलाफ धन शोधन का मामला नहीं बनता है। यह जालसाजी में प्रथम दृष्टया अपीलकर्ता की संलिप्तता की ओर भी इशारा नहीं करता है।

21. उपरोक्त के अलावा, इस मामले में एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठता है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि अपीलकर्ता एक अन्य ईसीआईआर, अर्थात् ईसीआईआर संख्या 4/2022 के संबंध में 25.08.2022 से न्यायिक हिरासत में है और न्यायिक हिरासत में रहते हुए उसकी गिरफ्तारी वर्तमान ईसीआईआर, अर्थात् ईसीआईआर संख्या 5 में 11.08.2023 को दिखाई गई थी। अपीलकर्ता के बयान 03.08.2023, 04.08.2023,11.08.2023, 12.08.2023, 14.08.2023, 15.08.2023 और 30.08.2023 को दर्ज किए गए थे।

22. प्रश्न यह उठता है कि जब कोई व्यक्ति उसी जाँच एजेंसी द्वारा जाँचे गए किसी अन्य मामले में न्यायिक हिरासत में है, तो क्या किसी नए मामले में दर्ज किए गए बयान (इस मामले में दिनांक 03.08.2023, 04.08.2023, 11.08.2023 के बयान) जिसमें उसकी गिरफ्तारी अभी तक नहीं दिखाई गई है, और जिसमें निर्माता के खिलाफ आपत्तिजनक सामग्री होने का दावा किया गया है, धारा 50 के तहत स्वीकार्य होंगे?

23. विजय मदनलाल चौधरी (सुप्रा) मामले में, धारा 50 के दायरे को संबोधित करते हुए, निम्नलिखित निर्णय दिया गया है:-

> "**159...** हालाँकि, यदि ईडी अधिकारी द्वारा औपचारिक गिरफ्तारी के बाद उसका बयान दर्ज किया जाता है, तो साक्ष्य अधिनियम की धारा 20(3) या धारा 25 के परिणाम लागू हो सकते हैं, जिससे यह आग्रह किया जा सकता है कि यह स्वीकारोक्ति की प्रकृति का है, इसलिए उसके खिलाफ साबित नहीं किया जाएगा।'

विजय मदनलाल चौधरी (सुप्रा) मामले में तीन न्यायाधीशों की पीठ ने अनुच्छेद 20(3) के अलावा साक्ष्य अधिनियम की धारा 25 का भी उल्लेख किया है। साक्ष्य अधिनियम की धारा 25 इस प्रकार है:-

"25. **पुलिस अधिकारी के समक्ष की गई संस्वीकृति साबित न की जाएगी।-** किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष की गई कोई भी संस्वीकृति किसी अपराध के अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध साबित नहीं की जाएगी।

24. विजय मदनलाल चौधरी (सुप्रा) ने हालांकि यह माना कि पी.एम.एल.ए के तहत अधिकारी पुलिस अधिकारी नहीं हैं, लेकिन उन्होंने एक ऐसे परिदृश्य की आशंका जताई जहाँ किसी मामले में, अभियुक्तों को साक्ष्य अधिनियम की धारा 25 के तहत संरक्षण प्रदान करना पड़ सकता है। न्यायालय ने कहा कि ऐसी स्थितियों की जाँच प्रत्येक मामले के आधार पर की जानी चाहिए। हम **विजय मदनलाल चौधरी (सुप्रा)** के पैरा 172 को उद्धृत करना उचित समझते हैं।

"172. दूसरे शब्दों में, इस न्यायालय द्वारा तूफान सिंह (सुप्रा) में निपटाए गए एनडीपीएस अधिनियम की योजना और विचाराधीन 2002 अधिनियम के प्रावधानों के बीच स्पष्ट अंतर है। **इस प्रकार, यह मानना होगा कि 2002 अधिनियम के तहत अधिकारी पुलिस अधिकारी नहीं हैं।** परिणामस्वरूप, 2002 अधिनियम के तहत अधिकारियों द्वारा दर्ज किए गए बयान, धन शोधन के अपराध में शामिल व्यक्तियों या पूछताछ/जांच के प्रयोजनों के लिए गवाहों के बयान, संविधान के अनुच्छेद 20(3) या उस मामले के लिए, अनुच्छेद 21 के तहत कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत प्रभावित नहीं हो सकते हैं। **किसी दिए गए मामले में, धन शोधन के अपराध के लिए मुकदमा चलाए जा रहे अभियुक्त को साक्ष्य अधिनियम की धारा 25 के तहत दी गई सुरक्षा उपलब्ध है या नहीं, इस पर साक्ष्य के नियम के रूप में मामला-दर-मामला आधार पर विचार करना पड़ सकता है।"**

(जोर दिया गया)

25. इस न्यायालय ने विजय मदनलाल चौधरी (सुप्रा) मामले में धारा 50 के तहत बयान दर्ज करते समय उत्पन्न होने वाली विभिन्न परिस्थितियों का पूर्वानुमान लगाया और उनसे निपटने के मानदंडों पर चर्चा की। राजाराम जायसवाल बनाम बिहार राज्य, एआईआर 1964 एससी 828, विजय मदनलाल चौधरी (सुप्रा) मामले में उद्धृत एक निर्णय में, इस न्यायालय ने कहा कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 25 में "पुलिस अधिकारी" शब्द केवल उन व्यक्तियों तक सीमित नहीं है जो नियमित रूप से गठित पुलिस बल के सदस्य हैं। इसके अलावा, साक्ष्य अधिनियम की धारा 25 के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी के "पुलिस अधिकारी" होने के निर्धारण के लिए परीक्षण निर्धारित करते हुए, इस न्यायालय ने राजाराम जायसवाल (सुप्रा) में (विजय मदनलाल चौधरी (सुप्रा) के पैरा 165 से उद्धृत) यह माना कि

"165(ii) यह अच्छी तरह से हो सकता है कि एक क़ानून एक लोक सेवक को शक्तियाँ प्रदान करता है और कर्तव्य आरोपित करता है, जिनमें से कुछ एक पुलिस अधिकारी के समान हैं। लेकिन अन्य कर्तव्यों की प्रकृति के कारण जिन्हें उसे करने की आवश्यकता होती है, वह कई अन्य शक्तियों का भी प्रयोग कर सकता है। राज्य की ओर से यह तर्क दिया जाता है कि जहाँ ऐसा मामला है, ऐसे व्यक्ति को पुलिस अधिकारी की केवल कुछ शक्तियों का प्रदत्त करना उसे पुलिस अधिकारी नहीं बनाता है और इसलिए, जो बात ध्यान में रखनी चाहिए वह है उन शक्तियों का कुल योग जो वह अपने पद के आधार पर प्राप्त करता है और साथ ही वह प्रमुख उद्देश्य जिसके लिए उसे नियुक्त किया गया है। इस प्रकार तर्क यह है कि जब एक अधिकारी को कई प्रकार के कर्तव्यों का पालन करना होता है और तदनुसार कई प्रकार की शक्तियों का प्रयोग करना होता है, तो मात्र यह तथ्य कि क़ानून द्वारा उसे प्रदान की गई शक्तियाँ पुलिस अधिकारी की शक्तियों के समान या समान भी हैं, तो भी वह पुलिस अधिकारी नहीं बनता और इसलिए, यदि ऐसा अधिकारी स्वीकारोक्ति दर्ज करता है, तो वह साक्ष्य अधिनियम की धारा 25 के अंतर्गत नहीं आएगा। हमारे निर्णय में, इस प्रावधान के प्रयोजनार्थ किसे 'पुलिस अधिकारी' माना जा सकता है, यह निर्धारित करने के लिए ध्यान में रखने योग्य बात यह नहीं है कि किसी अधिकारी को कितनी शक्तियाँ प्राप्त हैं, बल्कि यह है कि कानून उसे किन शक्तियों का प्रयोग करने में सक्षम बनाता है। साक्ष्य अधिनियम की धारा 25 के प्रयोजनार्थ ऐसा व्यक्ति "पुलिस अधिकारी" है या नहीं, यह निर्धारित करने का परीक्षण, हमारे निर्णय में, यह होगा कि क्या किसी पुलिस अधिकारी की शक्तियाँ, जो उसे प्रदान की गई हैं या जो उसके द्वारा प्रयोग की जा सकती हैं क्योंकि उसे पुलिस थाने का प्रभारी अधिकारी माना जाता है, धारा 25 द्वारा अधिनियमित निषेध, अर्थात, स्वीकारोक्ति दर्ज करने के साथ सीधा या पर्याप्त संबंध स्थापित करती हैं। **दूसरे शब्दों में, परीक्षण यह होगा कि क्या ये शक्तियाँ ऐसी हैं जो किसी संदिग्ध या अपराधी से स्वीकारोक्ति प्राप्त करने में उसकी सहायता करेंगी। यदि ऐसा है, तो उस प्रमुख उद्देश्य पर विचार करना अनावश्यक है जिसके लिए उसे नियुक्त किया गया है या यह प्रश्न कि उसे अन्य कौन-सी शक्तियाँ प्राप्त हैं। ये प्रश्न शायद विचारणीय हो सकते हैं जहाँ पुलिस अधिकारी द्वारा उसे प्रदान**

की गई शक्तियाँ बहुत सीमित प्रकृति की हैं और अपने आप में उसके द्वारा स्वीकारोक्ति प्राप्त करने में सहायता करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं।"

(जोर दिया गया)

26. चार दशक पहले, न्यायमूर्ति वी.आर. कृष्णा अय्यर ने अपनी अनोखी शैली में, **नंदिनी सत्पथी** बनाम **पी.एल. दानी एवं अन्य** (1978) 2 एससीसी 424 मामले में इस न्यायालय की ओर से बोलते हुए निम्नलिखित टिप्पणी की थी:-

"**50.** हालाँकि, हम अपराध की प्रवृत्ति का आकलन करने के लिए किसी दिए गए मामले की विशिष्ट सेटिंग के महत्व को रेखांकित करते हैं। **समान रूप से, हम प्रतिरक्षा के विस्तार पर आगामी अन्य जाँचों या लंबित अभियोजनों की बहुलता के प्रभाव को ध्यान में रखने की आवश्यकता पर बल देते हैं। "स्वयं के विरुद्ध गवाही देना" केवल उस विशेष अपराध तक सीमित नहीं है जिसके बारे में पूछताछ की जा रही है, बल्कि उन अन्य अपराधों तक भी लागू होता है जिनके बारे में अभियुक्त को अपने उत्तर से निहितार्थ की उचित आशंका है। यह निष्कर्ष "आपराधिक आरोप के संपर्क में आने की प्रवृत्ति" से भी निकलता है। "आपराधिक आरोप" में कोई भी आपराधिक आरोप शामिल है जो वर्तमान में जाँच या परीक्षण के अधीन है या जो अभियुक्त के लिए आसन्न खतरा है।"** (जोर दिया गया)

57. हमारा मानना है कि धारा 161 पुलिस को जाँच के दौरान अभियुक्त से पूछताछ करने का अधिकार देती है। अनुच्छेद 20(3) का निषेधात्मक प्रभाव पुलिस पूछताछ के चरण तक जाता है - जैसा कि तर्क दिया गया है, केवल अदालत में शुरू होने तक नहीं। हमारे निर्णय में, जहाँ तक पुलिस जाँच का संबंध है, अनुच्छेद 20(3) और धारा 161(1) के प्रावधान मूलतः एक ही क्षेत्र को कवर करते हैं। **एक जाँच या मुकदमे के दौरान आत्म-आरोप लगाने और मौन रहने के अधिकार पर प्रतिबंध, उस मामले से आगे जाता है और अभियुक्त को लंबित या आसन्न अन्य अपराधों के संबंध में सुरक्षा प्रदान करता है, जो उसे आपराधिक मामले का स्वेच्छा से खुलासा करने से रोक सकते हैं। हम 'बाध्य गवाही' को केवल शारीरिक धमकियों या हिंसा से प्राप्त साक्ष्य के रूप में नहीं, बल्कि मानसिक यातना, वायुमंडलीय दबाव, पर्यावरणीय दबाव, थकाऊ पूछताछ, दबंग और धमकाने वाले तरीकों आदि से प्राप्त साक्ष्य के रूप में देखते हैं** - उल्लंघन के लिए कानूनी दंड नहीं।

इसलिए, उत्तर देने से इनकार करने, या सच्चाई से उत्तर देने के बाद आने वाले कानूनी खतरों को नहीं माना जा सकता। अनुच्छेद 20(3) के अर्थ में बाध्यता के रूप में। अभियोजन की संभावना संवैधानिक अधिकार के प्रयोग में कानूनी तनाव पैदा कर सकती है, लेकिन फिर, चुप्पी साधे रखना एक सोची-समझी रणनीति है। **दूसरी ओर, यदि पुलिसकर्मी द्वारा किसी अभियुक्त से अपराध का स्पष्ट संकेत देने वाली जानकारी प्राप्त करने के लिए किसी भी प्रकार का दबाव, चाहे वह सूक्ष्म हो या अपरिष्कृत, मानसिक हो या शारीरिक, प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष, लेकिन पर्याप्त रूप से पर्याप्त हो, तो यह 'बाध्यकारी गवाही' बन जाती है, जो अनुच्छेद 20(3) का उल्लंघन है।**

27. वर्तमान मामले के तथ्यों को देखते हुए, हमारा मानना है कि यदि अपीलकर्ता के बयान को निर्माता के विरुद्ध अभियोगात्मक माना जाए, तो वह साक्ष्य अधिनियम की धारा 25 के अंतर्गत आएगा, क्योंकि उसने यह बयान न्यायिक हिरासत में रहते हुए, उसी जाँच एजेंसी द्वारा शुरू की गई एक अन्य कार्यवाही के तहत दिया है। चूँकि उसे बयान दर्ज करने के लिए न्यायिक हिरासत से बाहर लाया गया था, इसलिए अपीलकर्ता के विरुद्ध बयान को स्वीकार्य मानना न्याय का उपहास होगा।

28. अपीलकर्ता अभियुक्त को यह नहीं बताया जा सकता कि यह बयान देते समय:- "आपने 'ईसीआईआर 5/2023' शीर्षक में बताया है, न कि 'ईसीआईआर 4/2022' शीर्षक में।"

29. **विजय मदनलाल चौधरी (सुप्रा)** को पूरी तरह से पढ़ने पर, खासकर पैराग्राफ 159, 165 और 172, हमें खुद से यह सवाल पूछने के लिए मजबूर करते हैं: क्या यह तर्कसंगत अनुमान वैध रूप से संभव है कि अपीलकर्ता की कमज़ोर स्थिति और जाँच एजेंसी की प्रभावशाली स्थिति के कारण, दूसरी कार्यवाही में हुई गिरफ़्तारी के मद्देनज़र, स्वीकारोक्ति प्राप्त करने के लिए अनुकूल माहौल बना? हम निश्चित रूप से ऐसा ही मानते हैं। सवाल यह नहीं है कि क्या यह वास्तव में हुआ था। सवाल यह है कि क्या यह संभव हो सकता था।

30. मद्रास उच्च न्यायालय के दो पुराने निर्णयों से हमें इस दृष्टिकोण का समर्थन प्राप्त है। एलुकुरी शेषपानी चेट्टी (ILR 1937 Mad 358) मामले में न्यायमूर्ति मॉकेट ने न्यायमूर्ति जैक्सन के कोडंगी बनाम एम्परर (AIR 1932 Mad 24) मामले में दिए गए निर्णय के बाद निम्नलिखित निर्णय दिया:-

"मेरे फैसले में, जैसा कि मैंने पहले ही कहा है, यह स्पष्ट रूप से एक स्वीकारोक्ति है, और जैसा कि कोडंगी बनाम एम्परर (एआईआर 1932 मैड 24) में जे. जैक्सन ने बताया है, अपराध A की जाँच के दौरान पुलिस के सामने किया गया स्वीकारोक्ति, हालाँकि यह किसी अन्य अपराध B से संबंधित है, समान रूप से अस्वीकार्य है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 25 की पूरी भावना पुलिस के सामने दिए गए स्वीकारोक्ति को बाहर करना है और, जैसे ही कोई बयान स्वीकारोक्ति के बराबर पाया जाता है, मुझे नहीं लगता कि इससे ज़रा भी फर्क पड़ता है कि इसे किस अपराध का स्वीकारोक्ति कहा गया है।" (जोर दिया गया)

31. हमारा मानना है कि यहाँ निर्धारित सिद्धांत लागू होता है। वास्तव में, **विजय मदनलाल चौधरी (सुप्रा)** मामले में तीन न्यायाधीशों की पीठ ने, ऊपर उद्धृत पैरा में, व्यक्ति की हिरासत में दर्ज किए गए बयानों पर विचार करते समय साक्ष्य अधिनियम की धारा 25 का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है।

32. हमें यह मानने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि जब कोई अभियुक्त पी.एम.एल.ए के तहत हिरासत में हो, चाहे वह किसी भी मामले में हिरासत में हो, तो उसी जाँच एजेंसी को पी.एम.एल.ए की धारा 50 के तहत दिया गया कोई भी बयान, बयान देने वाले के विरुद्ध अस्वीकार्य है। इसका कारण यह है कि उसी जाँच एजेंसी द्वारा जाँच की गई कार्यवाही के तहत हिरासत में लिया गया व्यक्ति ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे स्वतंत्र मन से कार्य करने वाला माना जा सके। बयान देने वाले के विरुद्ध ऐसे बयानों को स्वीकार्य बनाना बेहद असुरक्षित होगा, क्योंकि ऐसा करना निष्पक्षता और न्याय के सभी सिद्धांतों के विपरीत होगा।

33. हम धारा 50 की संरचना से भी समर्थन प्राप्त करते हैं। धारा 50 इस प्रकार है:-

"धारा 50. समन, दस्तावेज और साक्ष्य आदि प्रस्तुत करने के संबंध में प्राधिकारियों की शक्तियां देता है ।

(1) धारा 13 के प्रयोजनों के लिए निदेशक को वही शक्तियां प्राप्त होंगी जो निम्नलिखित मामलों के संबंध में किसी वाद का विचारण करते समय सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के अधीन सिविल न्यायालय में निहित होती हैं, अर्थात्:-

(क) खोज और निरीक्षण;

(ख) रिपोर्टिंग इकाई के किसी भी अधिकारी सहित किसी भी व्यक्ति की उपस्थिति सुनिश्चित करना तथा शपथ पर उसकी जांच करना;

(ग) रिकॉर्ड के उत्पादन को बाध्य करना;

(घ) हलफनामों पर साक्ष्य प्राप्त करना;

(ङ) गवाहों और दस्तावेजों की जांच के लिए कमीशन जारी करना; और

(च) कोई अन्य मामला जो निर्धारित किया जा सकता है।

(2) निदेशक, अपर निदेशक, संयुक्त निदेशक, उप निदेशक या सहायक निदेशक को किसी भी व्यक्ति को बुलाने की शक्ति होगी, जिसकी उपस्थिति वह आवश्यक समझे, चाहे इस अधिनियम के तहत किसी जांच या कार्यवाही के दौरान साक्ष्य देने या कोई रिकॉर्ड पेश करने के लिए।

(3) इस प्रकार बुलाए गए सभी व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से या प्राधिकृत एजेंटों के माध्यम से उपस्थित होने के लिए बाध्य होंगे, जैसा कि अधिकारी निर्देश दे, और जिस भी विषय के संबंध में उनसे पूछताछ की जा रही हो, उस पर सत्य बताने या बयान देने के लिए बाध्य होंगे, और ऐसे दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए बाध्य होंगे, जिनकी आवश्यकता हो।

(4) उपधारा (2) और (3) के अधीन प्रत्येक कार्यवाही भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 193 और धारा 228 के अर्थ में न्यायिक कार्यवाही समझी जाएगी।

(5) केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त बनाए गए किसी नियम के अधीन रहते हुए, उपधारा (2) में निर्दिष्ट कोई अधिकारी इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही में उसके समक्ष प्रस्तुत किए गए किसी अभिलेख को, ऐसी अवधि के लिए, जितनी वह ठीक समझे, परिबद्ध कर सकेगा और अपनी अभिरक्षा में रख सकेगा:

बशर्ते कि सहायक निदेशक या उप निदेशक–

(क) ऐसा करने के कारणों को दर्ज किए बिना कोई भी रिकॉर्ड जब्त करना; या

(ख) संयुक्त निदेशक की पूर्व स्वीकृति के बिना, ऐसे किसी भी अभिलेख को तीन महीने से अधिक अवधि तक अपने पास नहीं रख सकेगा।"

धारा 50 (1)(ख) किसी भी व्यक्ति की उपस्थिति सुनिश्चित करने की बात करती है। धारा 50 (2) प्राधिकृत अधिकारियों को किसी भी व्यक्ति को, जिसकी उपस्थिति वे आवश्यक समझते हैं, चाहे वह साक्ष्य देने के लिए हो या अधिनियम के तहत किसी भी जाँच या कार्यवाही के दौरान कोई अभिलेख प्रस्तुत करने के लिए हो, बुलाने की शक्ति रखती है। धारा 50 (3) में कहा गया है कि इस प्रकार बुलाए गए सभी व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से या अधिकृत एजेंटों के माध्यम से, जैसा कि अधिकारी निर्देश दे, उपस्थित होने के लिए बाध्य होंगे और जिस विषय पर उनकी जाँच की जा रही है, उस पर सत्य कथन करने या बयान देने तथा ऐसे दस्तावेज़ प्रस्तुत करने के लिए बाध्य होंगे। धारा 50(4) में कहा गया है कि उप-धारा (2) और (3) के अंतर्गत प्रत्येक कार्यवाही न्यायिक कार्यवाही मानी जाएगी। न्यायिक हिरासत में बंद व्यक्ति, स्वतंत्र व्यक्ति न होने के कारण, उसे बुलाया नहीं जा सकता और दर्ज किया जाने वाला कोई भी बयान उस न्यायालय की अनुमति प्राप्त करने के बाद ही दर्ज किया जाएगा जिसने उसे दूसरे मामले में न्यायिक हिरासत में भेजा है।

34. उपरोक्त के मद्देनजर और अनुच्छेद 21 के हितकारी सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए, हम मानते हैं कि चूंकि अनुच्छेद 21 में आने वाले शब्द 'कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया' एक उचित और वैध प्रक्रिया है, इसलिए धारा 50 के तहत अपीलकर्ता के बयान पर ई.सी.आई.आर संख्या 5/2023 में अपीलकर्ता के खिलाफ भरोसा नहीं किया जा सकता है, भले ही अपीलकर्ता उस समय ई.सी.आई.आर संख्या 4/2022 में हिरासत में था।

<u>सह-अभियुक्त अफसर अली का बयान</u>

35. अपीलकर्ता का नाम एफआईआर संख्या 399/2023 में नहीं था। प्रतिवादी-प्रवर्तन निदेशालय की शिकायत के पैरा 6 से ऐसा प्रतीत होता है कि अफशर अली, सद्दाम हुसैन, इम्तियाज अहमद को 14.04.2023 को ई.सी.आई.आर/आर.एन.जेड.ओ 18/2022 में गिरफ्तार किया गया था, हालांकि पैरा 8.12 में बयानों के सारांश में उल्लेख किया गया है कि अफशर अली को 14.04.2023 को गिरफ्तार किया गया था, जिसे शिकायत की प्रार्थना (सी) के साथ पढ़ने पर ऐसा प्रतीत होता है कि पैरा 8.12 में जिस गिरफ्तारी का उल्लेख किया गया है, वह ई.सी.आई.आर/ आर.एन.जेड.ओ 18/2022 में गिरफ्तारी है।

36. आरोपी अफशर अली को 14.04.2023 को ई.सी.आई.आर/आर.एन.जेड.ओ 18/2022 (एक अलग ई.सी.आई.आर) में गिरफ्तार किया गया था और उसका बयान 17.04.2023 को वर्तमान ई.सी.आई.आर में दर्ज किया गया था। अफशर अली ने कहा है कि जब से उसे पता चला कि जमीन पुलिस की निगरानी में है और जमीन को लेकर कुछ विवाद हैं, उसने अपीलकर्ता से मुलाकात की और अपीलकर्ता को विवादों और पुलिस की सतर्कता के बारे में बताया गया। अफशर

अली के बयान के अनुसार, अपीलकर्ता ने जमीन की स्थिति का जायजा लिया और तत्कालीन उपायुक्त छवि रंजन को बुलाया और उन्हें बताया कि पुलिस द्वारा देखी गई सतर्कता को हटाने के बाद चेशायर होम संपत्ति की रजिस्ट्री की जानी है। इसके बाद, अपीलकर्ता ने रुपये का प्रतिफल तय किया। 1.5 करोड़ रुपये की राशि तय होने के बाद, उन्होंने अपीलकर्ता से उपायुक्त कार्यालय द्वारा अवरुद्ध किए गए दो भूखंडों को खुलवाने का अनुरोध किया। अपीलकर्ता ने उपरोक्त कार्य के लिए 1 करोड़ रुपये की मांग की थी और यह राशि उक्त राशि में समायोजित कर दी गई थी और अपीलकर्ता ने ही पुनीत भार्गव के नाम पर पंजीकरण करने का अनुरोध किया था। उन्होंने यह भी कहा कि अपीलकर्ता ने ही बिष्णु कुमार अग्रवाल के साथ सौदा तय किया था।

37. अपीलकर्ता के साथ सह-अभियुक्त होने के नाते, अपीलकर्ता के विरुद्ध उसका बयान, यह मानते हुए कि वर्तमान अपीलकर्ता के विरुद्ध कोई अभियोगात्मक तथ्य मौजूद है, ठोस साक्ष्य का स्वरूप नहीं रखेगा। अभियोजन पक्ष अपना मामला स्थापित करने के लिए ऐसे बयान से शुरुआत नहीं कर सकता। हमारा मानना है कि ऐसी स्थिति में, सह-अभियुक्त के इकबालिया बयान पर विचार करते समय इस न्यायालय द्वारा साक्ष्य अधिनियम की धारा 30 के तहत निर्धारित कानून लागू रहेगा। **कश्मीरा सिंह बनाम मध्य प्रदेश राज्य** [1952] एस.सी.आर 526 में, इस न्यायालय ने इस सिद्धांत को स्पष्ट रूप से इस प्रकार संक्षेपित किया:-

> "....इस तरह के मामले को देखने का उचित तरीका यह है कि सबसे पहले, अभियुक्त के खिलाफ सबूतों को इकट्ठा किया जाए, जिसमें स्वीकारोक्ति को पूरी तरह से विचार से बाहर रखा जाए और देखा जाए कि अगर उस पर विश्वास किया जाता है, तो क्या उसके आधार पर दोषसिद्धि सुरक्षित रूप से की जा सकती है। अगर स्वीकारोक्ति से स्वतंत्र रूप से विश्वास किया जा सकता है, तो बेशक स्वीकारोक्ति को सहायता के रूप में लेना आवश्यक नहीं है। लेकिन ऐसे मामले सामने आ सकते हैं जहाँ न्यायाधीश अन्य सबूतों के आधार पर कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है, भले ही अगर उन पर विश्वास किया जाए, तो वे दोषसिद्धि को बनाए रखने के लिए पर्याप्त होंगे। ऐसी स्थिति में न्यायाधीश स्वीकारोक्ति को सहायता के रूप में ले सकता है और इसका उपयोग अन्य सबूतों को आश्वासन देने के लिए कर सकता है और इस प्रकार खुद को उस बात पर विश्वास करने के लिए मजबूत कर सकता है जिसे स्वीकारोक्ति की सहायता के बिना वह स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होगा।"

इसलिए, जहां तक अफसर अली के बयान का सवाल है, जांच एजेंसी को पहले अन्य साक्ष्यों को जुटाना होगा और अधिक से अधिक आश्वासन के लिए बयान पर गौर करना होगा।

स्वतंत्र रूप से, अफसर अली का बयान प्रथम दृष्टया बिक्री विलेख और अन्य दस्तावेजों की जालसाजी में अपीलकर्ता की भूमिका या धन शोधन के अपराध में शामिल होने के बारे में कुछ भी संकेत नहीं देता है।

राजदीप कुमार का बयान

38. हमने शिकायत में संक्षेप में दिए गए राजदीप कुमार के बयान का अध्ययन किया है। राजदीप कुमार ने केवल इतना कहा है कि वह अपीलकर्ता के लिए काम करते थे और चेशायर होम स्थित एक ज़मीन के सौदे के सिलसिले में अपीलकर्ता द्वारा अफ़शर अली के घर पर उनसे परिचय कराने के बाद उनकी मुलाक़ात अफ़शर अली से हुई थी। उन्होंने आगे बताया कि उन्होंने सद्दाम हुसैन से भी अपीलकर्ता के घर पर उक्त ज़मीन पर मुलाक़ात की थी। उन्होंने आगे बताया कि उन्होंने अफ़शर अली और सद्दाम हुसैन के करीबी सहयोगियों इम्तियाज़ अहमद और भरत प्रसाद को भी देखा था। प्रथम दृष्टया, हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि पी.एम.एल.ए की धारा 3 और 4 के तहत अपराध के लिए अपीलकर्ता को दोषी ठहराने के लिए कोई सबूत नहीं है।

सह-अभियुक्त मोहम्मद सद्दाम हुसैन का बयान

39. मो. सद्दाम हुसैन को 14.04.2023 को ई.सी.आई.आर/आर.एन.जेड.ओ 18/2022 (एक अलग ई.सी.आई.आर) में भी गिरफ्तार किया गया था, वर्तमान ईसीआईआर में 26.04.2023 के अपने बयान में उन्होंने केवल राजदीप कुमार को जानने और 3.81 एकड़ जमीन के टुकड़े को खोलने के उद्देश्य से उनसे मिलने और राजदीप कुमार द्वारा तत्कालीन डिप्टी कमिश्नर - छवि रंजन के साथ एक बैठक की व्यवस्था करने की बात कही है। अफशर अली के बयान की तरह उनके बयान को भी ठोस सबूत होने का दर्जा नहीं होगा और जहां तक सह-अभियुक्तों का संबंध है, यह अफशर के बयान जैसा ही होगा। शिकायत में अभियोजन पक्ष ने अनुमान लगाया है कि यह राजदीप कुमार ही थे जो डिप्टी कमिश्नर, छवि रंजन और प्रेम प्रकाश के बीच की कड़ी थे और जिन्होंने अपीलकर्ता - प्रेम प्रकाश के निर्देश पर काम किया और सद्दाम हुसैन को जमीन को खोलने में मदद की उपरोक्त बयान की न्यायिक हिरासत में दर्ज किए गए 29.08.2023 के उनके आगे के बयान से प्राप्त पुष्टि अभियोजन पक्ष को समर्थन देने के लिए इस तथ्य के अलावा और कुछ नहीं जोड़ती है कि 29.08.2023 के बयान में ठोस सबूत के चरित्र का अभाव था।

पुनीत भार्गव का बयान

40. जहां तक पुनीत भार्गव के बयान का संबंध है, यह 09.12.2022 को दर्ज किया गया था। उन्होंने कहा है कि वह बिष्णु अग्रवाल को मार्च, 2021 से जानते हैं, जब अपीलकर्ता के निर्देश पर उन्होंने बिष्णु अग्रवाल को 1 एकड़ जमीन बेची थी। उन्होंने आगे कहा है कि उन्होंने प्रेम प्रकाश की देखरेख में जमीन का टुकड़ा खरीदा था और प्रेम प्रकाश के निर्देशों के तहत, उन्होंने अपने नाम पर एक जमीन हासिल की और तदनुसार अपीलकर्ता के निर्देश पर, उन्होंने इसे बिष्णु कुमार अग्रवाल को

बेच दिया। उन्होंने कहा कि अपीलकर्ता के निर्देश पर, उन्होंने चेक के माध्यम से राजेश राय को 25 लाख रुपये दिए, जिसके बाद संपत्ति का पंजीकरण और म्यूटेशन किया गया, लेकिन आगे कहा कि शेष राशि को बाद में भुनाने के लिए छह पोस्टडेटेड चेक दिए गए थे। उन्होंने आगे कहा है कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है कि पंजीकरण और म्यूटेशन के बाद भी बाकी भुगतान क्यों नहीं किया गया और अपीलकर्ता शायद इसका जवाब दे सकते हैं। जब उनसे पूछा गया कि जब संपत्ति दो महीने के भीतर ही बिष्णु अग्रवाल को बेच दी गई तो उनके नाम पर संपत्ति क्यों खरीदी गई, तो उन्होंने कहा कि यह केवल प्रेम प्रकाश के निर्देश पर किया गया था।

41. बयान में उल्लेख किया गया है कि 25 लाख रुपये के अलावा, छह पोस्ट-डेटेड चेक भी दिए गए थे। इसके बाद, इसमें केवल अपीलकर्ता द्वारा ज़मीन की खरीद-बिक्री की सलाह देने की बात कही गई है। प्रथम दृष्टया, ये हमारे इस विश्वास के उचित आधार को कम नहीं करते कि अपीलकर्ता धारा 3 और 4 के तहत अपराध का दोषी नहीं है।

बिष्णु कुमार अग्रवाल (ए9) जमानत पर - आदेश अंतिम हो गया है

42. हम, प्रथम दृष्टया, पाते हैं कि अपीलकर्ता के बयानों और जांच एजेंसी द्वारा भरोसा किए गए अन्य बयानों और अन्य सामग्री से, ऐसा कुछ भी संकेत नहीं मिलता है कि याचिकाकर्ता जाली विलेख के निर्माण में शामिल था और न ही उसे 1948 के जाली विक्रय विलेख की कोई जानकारी थी। बिष्णु कुमार अग्रवाल को जमानत पर रिहा करने के आदेश में यह देखा गया कि-यह मानना उचित है कि बिष्णु कुमार अग्रवाल वर्तमान मामले में संबंधित संपत्ति के वास्तविक क्रेता थे। इसमें यह भी माना गया है कि बिक्री प्रतिफल बाद में बनाने और बिक्री का पंजीकरण पहले करने में बिष्णु कुमार अग्रवाल के विरुद्ध कोई आपराधिकता नहीं पाई जा सकती थी। संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम की धारा 54 का हवाला दिया गया है। इसी आदेश में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दर्ज शिकायत के पैरा 10.6.6 का भी उल्लेख किया गया है, जिसमें उल्लेख किया गया है कि प्रवर्तन निदेशालय की जाँच से पता चला है कि एफआईआर संख्या 399/2022 में शिकायतकर्ता, उमेश कुमार गोप, स्वयं उक्त संपत्ति पर अपना दावा बेतुका ढंग से पेश कर रहे थे। बहरहाल, बिष्णु कुमार अग्रवाल को दी गई ज़मानत का आदेश अंतिम हो गया है।

43. इसके अलावा, रिकॉर्ड में ऐसी कोई सामग्री नहीं है जिससे यह पता चले कि किस आधार पर यह दावा किया गया है कि मेसर्स जामिनी एंटरप्राइजेज में लाभकारी हित अपीलकर्ता के पास है। इसलिए, जिन बयानों पर भरोसा किया गया है, उनसे प्रथम दृष्टया अपीलकर्ता के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला नहीं बनता।

44. शिकायत में दो अन्य लेन-देनों का भी उल्लेख है जिनकी जाँच बिष्णु कुमार अग्रवाल के विरुद्ध की जा रही है। अभिलेखों से अपीलकर्ता की संलिप्तता और बिष्णु कुमार अग्रवाल से संबंधित अन्य लेन-देनों के संबंध में उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही शुरू करने के बारे में कुछ भी पता नहीं चल पाया है।

45. इस परिदृश्य में, हम मानते हैं कि अपीलकर्ता ने धारा 45 के तहत दोहरी शर्तों को पूरा किया है। रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री के आधार पर, यह न्यायालय संतुष्ट है कि यह मानने के लिए उचित आधार हैं कि अपीलकर्ता पी.एम.एल.ए की धारा 3 और 4 के तहत कथित मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध का दोषी नहीं है और न्यायालय आगे संतुष्ट है कि यदि अपीलकर्ता को जमानत पर रिहा किया जाता है तो उसके द्वारा कोई अपराध किए जाने की संभावना नहीं है।

<u>आपराधिक पूर्ववृत्त के बारे में तर्क.</u>

46. जांच एजेंसी ने आपराधिक पूर्ववृत्त के रूप में ईसीआईआर संख्या 4 का भी उल्लेख किया है। साहेबगंज, झारखंड में अवैध पत्थर खनन और संबंधित गतिविधियों से संबंधित ई.सी.आई.आर संख्या 4/2022 का संदर्भ दिया गया, जहां याचिकाकर्ता को 25.08.2022 को गिरफ्तार किया गया था और अभियोजन पक्ष की शिकायत 16.09.2022 को दायर की गई थी। जहां तक ई.सी.आई.आर संख्या 4/2022 से संबंधित जमानत का सवाल है, जो इस न्यायालय में एस.एल.पी (आपराधिक) संख्या 691/2023 में नोटिस के बाद लंबित है, उस मामले में जमानत के गुण-दोष की स्वतंत्र रूप से जांच की जाएगी। ई.सी.आई.आर संख्या 5/2023 से उत्पन्न वर्तमान मामले के तथ्यों की जांच करने और ऊपर दर्ज निष्कर्षों के मद्देनजर, हमें नहीं लगता कि अपीलकर्ता को अन्य मामले के लंबित होने के आधार पर जमानत से वंचित किया जा सकता है। हम वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए ऐसा कह रहे हैं क्योंकि हमें उसकी निरंतर हिरासत का कोई औचित्य नहीं दिखता। अपीलकर्ता पहले ही एक वर्ष से अधिक समय से हिरासत में है। मुकदमा अभी शुरू होना बाकी है। एक और ई.सी.आई.आर का संदर्भ है जिसका उल्लेख जाँच एजेंसी ने अपने प्रतिवाद में किया है, अर्थात् ई.सी.आई.आर/आर.एन.जेड.ओ/18/2022, लेकिन रिकॉर्ड से यह पता नहीं चलता कि अपीलकर्ता के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है या नहीं।

प्रेम प्रकाश बनाम
भारतीय यूनियन माध्यम प्रवर्तन निदेशालय

अपीलकर्ता द्वारा जेल सुविधाओं के दुरुपयोग का आरोप

47. अपीलकर्ता के आचरण के बारे में विस्तृत तर्क दिए गए हैं कि उसे जेल में कुछ सुविधाएँ दी गई हैं। हम उन पर कोई टिप्पणी नहीं करते हैं और यदि जेल नियमों का कोई उल्लंघन हुआ है, तो जाँच एजेंसी को जेल के उच्च अधिकारियों के समक्ष इस मुद्दे को उठाना चाहिए। वर्तमान मामले के तथ्यों के आधार पर, ये तर्क अपीलकर्ता को उसकी स्वतंत्रता से वंचित करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं।

48. ऊपर बताए गए कारणों से, अपील को अनुमति देते हुए, हम बी.ए. संख्या 9863/2023 में झारखंड उच्च न्यायालय रांची के दिनांक 22.03.2024 के निर्णय को रद्द करते हैं। हम स्पष्ट करते हैं कि इस निर्णय में की गई टिप्पणियां केवल जमानत आवेदन के निपटारे के उद्देश्य के लिए हैं और वे ट्रायल कोर्ट को प्रभावित नहीं करेंगी, जो कानून के अनुसार और रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्य के आधार पर आगे बढ़ेगी।

निष्कर्ष

49. परिणाम में, हम निम्नलिखित आदेश पारित करते हैं:-

I. अपील स्वीकार की जाती है और दिनांक 22.03.2024 का आदेश निरस्त किया जाता है।

II. ट्रायल कोर्ट को निर्देश दिया जाता है कि वह अपीलकर्ता को ईडी केस संख्या ईसीआईआर संख्या 5/2023 के संबंध में 5 लाख रुपये की राशि के जमानत बांड और समान राशि के 2 जमानती प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा करे।

III. अपीलकर्ता को अपना पासपोर्ट ट्रायल कोर्ट में जमा करना होगा और अपीलकर्ता को प्रत्येक सोमवार और गुरुवार को सुबह 10 से 11 बजे के बीच जांच अधिकारी को रिपोर्ट करना होगा।

IV. अपीलकर्ता गवाहों को प्रभावित करने और साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ करने का कोई प्रयास नहीं करेगा।

लंबित आवेदनों का निपटारा कर दिया जाएगा।

मामले का परिणाम: अपील स्वीकार की गई।

यह अनुवाद सुश्री लीना मुखर्जी, पैनल अनुवादक के द्वारा किया गया।